मंच पर ना अशोक गहलोत को तवज्जो मिली, ना सचिन पायलट को नकारा गया

रायपुर अधिवेशन के मंच से यह संदेश देकर आलाकमान ने राजस्थान में बैलैंस कायम रखा

- कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों में से 2 के मुख्यमंत्रियों को वक्ता के रूप में मौका दिया गया, पर, गहलोत को नहीं।
- बताया जा रहा है कि, 25 दिसम्बर 2022 के घटनाक्रम को लेकर आलाकमान आज भी सहज नहीं हो पाया है।
- ऐसे में चुनाव से पहले संभावित बदलाव पर सभी की नजरें टिकी हैं।

जयपुर, 28 फरवरी (का.प्र.)। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन से पहले राजस्थान में फेरबदल को लेकर चर्चाएं बहुत तेज थी, कि अधिवेशन के बाद राजस्थान के मामले में कांग्रेस आलाकमान निर्णय लेगा। अब अधिवेशन की समाप्ति के बाद सभी की नज़रें इसी पर हैं कि राजस्थान कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है।

वैसे रायपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान के मामले को लेकर आलाकमान ने सावधानी बरतते हुए, ना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंच पर बोलने का मौका दिया और ना ही सचिन पायलट को। वही मंच पर होने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दर्शक की मुद्रा में ही रहे। हां राजस्थान से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी अवश्य किसानों के मुद्दे पर बोले और यही राजस्थान का एकमात्र प्रतिनिधित्व रहा। दरअसल ऐसा करके राजस्थान के मसले पर पार्टी आलाकमान ने बैलेंस बनाने का प्रयास किया, ताकि किसी एक नेता के पक्ष में कोई संदेश नहीं जाए।

वैसे भी राजस्थान में 11 मार्च तक वर्तमान बजट सत्र समाप्त हो जाएगा और तब तक राजस्थान में बदलाव को लेकर जो भी फैसला लेना है, उस पर भी दिल्ली चर्चा कर चुकी होगी। उसके बाद राजस्थान में चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा।

चर्चा थी कि रायपुर अधिवेशन में राजस्थान पर चर्चा होगी, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन होने के कारण वहां किसी एक प्रदेश की चर्चा किया जाना संभव नहीं था। चर्चा सिर्फ इस बात की हुई कि जब कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों में से दो, मेजबान के नाते भूपेश बघेल और मेहमान के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंच से बोलने का मौका दिया गया, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत को मंच पर होने के बावजूद बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह इस बात का संकेत है कि पार्टी आलाकमान किसी एक पक्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। जहां तक मंच पर मौजूदगी की बात है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मंच पर मौजूद थे जब कि सचिन पायलट को मात्र साधारण विधायक होने के बावजूद भी मुख्य मंच पर स्थान दिया गया, यानी कि इस बात से आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल राजस्थान को लेकर वह किसी एक नेता पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वैसे नए बदलाव को लेकर बहुत कुछ उस वक्त भी स्पष्ट होगा जब कांग्रेस की नई कार्यसमिति में नेताओं के नाम तय कर लिए जाएंगे।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार ऐसा करके कांग्रेस आलाकमान ने यह भी दिखाने का प्रयास किया किया है कि 25 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम जयपुर में हुआ, वह अभी भी आलाकमान की नज़रों में है। यही कारण रहा कि उस मामले में शामिल माने जा रहे तीन नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को ए.आई.सी.सी. का डैलिगेट नहीं बनाया गया।

जबकि ए.आई.सी.सी. डेलिगेट्स की राजस्थान की सूची में कई छुटभैये नेताओं को भी मौका दिया गया है। अब भले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा यह बात प्रचारित करता रहे कि 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम के बावजूद उसके खेमे के किसी भी नेता को दंडित नहीं किया गया, लेकिन दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि अभी तक तीनों नेताओं को माफी भी नहीं दी गई है और कार्यवाही पेंडिंग है। कहा यही जा रहा है कि इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अधिवेशन के मंच से बोलने का मौका नहीं दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब अशोक गहलोत पार्टी के किसी अधिवेशन में मंच पर होने के बावजूद वक्ताओं में शामिल नहीं थे।

इन तमाम चर्चाओं और घटनाक्रमों के बीच कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र होते ही पार्टी आलाकमान दोनों खेमों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अपना फार्मूला सामने लाएगा। उस फार्मूले के तहत सत्ता और संगठन में अंतिम समय में जो संभावित बदलाव हो सकते हैं, उस बारे में फैसला लिया जाएगा। यही कारण है कि पार्टी के 85 वें अधिवेशन में राजस्थान के नेताओं को बराबर तवज्जो दी गई है, ताकि किसी तरह की नई चर्चाएं जन्म ना लें सकें।

'जम्मू को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी के मुख्य संरक्षक तथा स्व. भीम सिंह के सुपुत्र हैं, ने माँग की है कि वर्तमान जम्मू डिवीजन को भारत का 29वाँ राज्य बनाकर, उसका नाम डोगरास्तान रख दिया जाये।

एक बयान में वे कहते हैं कि भारतीय विरासत तथा इतिहास का सच्चे अर्थों में गुणगान करते समय भारत को डोगरस्तान की अस्मिता को पहचानना ही चाहिये। वे लिखते हैं कि भारतीय गणतंत्र के सभी नागरिकों को इस बात से अवगत होना चाहिये कि डोगरा समुदाय का इतिहास बड़ा लम्बा और सम्मोहक रहा है। उनके अनुसार, उनके पूर्वज राजा ध्यान सिंह डोगरा सिख साम्राज्य के सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। उनके परदादा के परदादा जनरल ज़ोरावर सिंह, जो "भारत के नेपोलियन" के रूप में प्रसिद्ध थे, भारत के सबसे यशस्वी मिलिटरी कमाण्डर थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में हिमालय क्षेत्र के बहुत ऊँचाई पर स्थित क्षेत्रों पर अपनी विजय-पताका फहराई थी, जिनमें लद्दाख एवं तिब्बत जैसे बौद्ध राज्य भी शामिल हैं। वे कहते हैं कि "सिकन्दर महान भी डोगराओं से ज्यादा महान नहीं था तथा स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, उसे 323 बी.सी. में चन्द्रभागा नदी के तट पर एक डोगरा के तीर ने ही रोक दिया था।"

अंकित ने जोर देते हुये कहा, "अब समय आ गया है कि जम्मू तथा कश्मीर को अलग-अलग कर दिया जाये, जिससे हम, भारत के लोग मंदिरों की भूमि, डोगरास्तान की सच्चे अर्थों में कद्र कर सकें तथा खासतौर से हमारी श्रद्धा की सबसे बड़ी केन्द्र वैष्णो देवी के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकें जिनका मंदिर पैन्थर्स पार्टी के गढ़ ऊधमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में स्थित है तथा जहाँ प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा हिन्दू तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते हैं। जम्मू को डोगरस्तान नाम दिया जाना बहुत ही अच्छा अनुभव होगा तथा इससे सभी लोग आनंदित होंगे। ऐसा माना जाता है कि डोगरा सम्राट भगवान सूर्य के सूर्यवंशी कुल के थे तथा उन्होंने जम्मू में हजारों साल तक शासन किया था। ज्ञातव्य है कि भगवान राम भी सूर्यवंशी थे।"

पाक ड्रोन को बी.एस.एफ. ने फायरिंग कर खदेड़ा

अनूपगढ़ के पास बॉर्डर पर पाक ड्रोन से हेरोइन तस्करी का प्रयास किया गया था

- प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट खमीसा और पृथ्वीसर के पिलर संख्या 355/2 एस और 355/3 एस पर रात को लगभग 3 बजे ड्रोन की आवाज आने पर जवानों ने ड्रोन को निशाना बनाते हुए 15 से 20 राउण्ड फायरिंग की।

अनूपगढ़, 28 फरवरी (कासं)। भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हेरोइन की तस्करी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। सीमा सुरक्षा बल की खमीसा पोस्ट और पृथ्वीसर पोस्ट के बीच ड्रोन की आवाज आने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की और खदेड़ दिया। घटना बीती रात लगभग तीन बजे की बताई जा रही है। मामला पुलिस थाना क्षेत्र समेजा कोठी को है इसलिए समेजा पुलिस को भी सूचना दी गई।

पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग ने बताया कि ग्राम पंचायत 21 एसजेएम के गांव खमीसा पर सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट खमीसा और पृथ्वीसर के पिलर संख्या 355/2 एस और 355/3 एस पर रात लगभग 3 बजे ड्रोन की आवाज सुनाई दी। सीमा पर तैनात जवानों ने ड्रोन को निशाना बनाते हुए 15 से 20 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और पुलिस को दी गई।

सूचना पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ थानाधिकारी फूलचंद शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में चर्चा कर पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हेरोइन की तस्करी की संभावना के चलते हेरोइन के पैकेट्स की तलाश और संदिग्ध व्यक्ति की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान भी चलाया। अभी तक किसी भी प्रकार का मलबा या मादक पदार्थों के पैकेट्स नहीं मिले है। वहीं पूरे जिले के सीमावर्ती क्षेत्र समेजा कोठी, बांडा कॉलोनी, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में भी नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है।

पंजाब के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानूनी राय लेने के बाद ही 3 मार्च को प्रस्तावित राजय के बजट सत्र की अनुमति दिए जाने के बारे में निर्णय लेंगे। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से सिफारिश की थी कि 3 से 24 मार्च तक बजट सत्र आयोजित किया जाए। उसने एक पत्र भी लिखा था जिसमें राज्यपाल की मंजूरी मांगी गई थी। इस पत्र के जवाब में राज्यपाल पुरोहित ने इन ट्वीट्स और पत्र का भी हवाला दिया जो मुख्यमंत्री ने 13 और 14 फरवरी को लिखे थे। राज्यपाल ने कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जाने पर सवाल खड़े करते हुए गत 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की थी। सरकार ने इस संबंध में कुछ सप्ताह पूर्व निर्णय लिया था। राज्यपाल का मानना है कि सिंगापुर ट्रेनिंग के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। राज्यपाल ने एक दागी व्यक्ति को पंजाब इन्फोटैक का चैयरमैन नियुक्त किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया था कि उक्त व्यक्ति सम्पत्ति हड़पने और अपहरण के केसों में आरोपी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से कहा था कि वह प्राचार्यों को सिंगापुर भेजने की समूची चयन प्रक्रिया और मापदण्ड से उन्हें अवगत करवाए क्योंकि इसमें पारदर्शिता ना बरते जाने के आरोप हैं।

15 साल पुराने केस में लालू यादव व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप से प्रसाद तथा उनके परिवार के सदस्यों को जमीनें औने-पौने दामों पर बेची थीं या उपहार में दी थीं। एफ.आई.आर. में आरोप लगाया गया था कि पटना में 1,05,292 वर्ग फीट जमीन पाँच सेल डीड्स तथा दो गिफ्ट डीड के जरिये प्रसाद के परिजनों ने अधिगृहीत कर ली थी तथा यह जमीन उन लोगों द्वारा दी गई थी, जिन्हें इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) में नौकरियाँ दी गई थीं। सी.बी.आई. ने अपनी चार्ज शीट में दावा किया है कि उसके पास प्रसाद तथा परिजनों को किये गये भुगतान के साक्ष्य हैं।

जहाँ प्रसाद के परिजन एक निडर मोर्चा (ब्रेव फ्रंट) प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ऐसी संभावना है कि सी.बी.आई. द्वारा इस केस को पुनः खोलने से आर.जे.डी. के खिलाफ "जंगल राज" के आरोप फिर से जोर-शोर से लगाये जायेंगे तथा प्रसाद और उनके परिजनों को इस केस से पूरी तरह बाँध दिये जाने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रसाद का स्वास्थ्य लम्बे समय से खराब है तथा वे राजनीति से करीब-करीब सेवानिवृत्त होने की स्थिति में हैं। इसलिये यह भी संभव है कि इस 15 साल पुराने केस पर सी.बी.आई. द्वारा इतना ज्यादा जोर दिया जाना लालू प्रसाद के समर्थकों तथा मतदाताओं को "बदले की राजनीति" नज़र आये।

'सरकार बताए, आर.पी.एस.सी. का मूल पेपर कहां से लीक हुआ?'

सी.एम. के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में गहलोत सरकार को घेरा

- संयम लोढ़ा ने कहा, "क्या आपने तय कर लिया है कि, नकल करने वाले ही सरकारी नौकरी में सलैक्ट होंगे।"
- संयम लोढ़ा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और पूछा "कुछ साल की नौकरी में दिव्या मित्तल ने 50 करोड़ का रिसॉर्ट कैसे बना लिया?।"
- संयम लोढ़ा ने कहा कि, संघ प्रमुख मोहन भागवत के उदयपुर दौरे के समय उनसे 20 लोग मिलने आए, जिसमें आदर्श घोटाले का मुख्य आरोपी भी था, इसकी जांच होनी चाहिए।

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर 28 फरवरी। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक मुद्दे पर सदन में गहलोत सरकार को घेरा। पुलिस और अनुदान की मांगों पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा ने कहा, पेपर लीक गंभीर मामला है। सरकार कम से कम यह तो बताए कि आर.पी.एस.सी. का पेपर कहां से लीक हुआ? इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, यह सब हमें समझ में आता है, लेकिन मूल पर्चा कहां से लीक हुआ, सरकार आज तक यह बताने की स्थिति में नहीं है। लोढ़ा ने कहा, हमारी भर्ती परीक्षाओं के हाल देखिए। अभी जोधपुर के एक कोचिंग सेंटर ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा पास करने वाले कुछ कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू किए। ऐसी-ऐसी लड़कियां सब इंस्पेक्टर में सलेक्ट हुई हैं, जिन्हें यह नहीं पता कि राजस्थान में कितने जिले हैं? क्या आपने तय कर लिया है कि नकल करने वालों को ही भर्ती करोगे। जो पेपर लीक कोटे से पेपर पास कर ले, उनको पास कर देते हो।

संयम लोढा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। संयम लोढ़ा ने कहा, रिश्वत के मामले में पकड़ी गई एस.ओ.जी. की अफसर दिव्या मित्तल का केस कई सवाल खड़े करता है। जब वह अफसर आर.ए.सी. में थी तो लंबे समय गैरहाजिर रही। उस पर फैसला आर.ए.सी. के अफसर की जगह एस.ओ.जी. में क्यों हुआ? उसने चंद साल की नौकरी में 50 करोड़ का रिसॉर्ट कैसे बना लिया? संयम लोढ़ा ने कहा कि, क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज की धोखाधड़ी के शिकार लोग आज भी अपने पैसों के लिए भटक रहे हैं। पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब उदयपुर दौरे पर थे तो आदर्श घोटाले के मुख्य आरोपी ने उनसे मुलाकात की थी। भागवत से मिलने वाले 20 लोगों में आदर्श घोटाले का मुख्य आरोपी भी था। अगर सरकार पूरी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहती है तो उदयपुर के प्रशासन से उनसे मिलने वालों का ब्यौरा लिया जा सकता है, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि अरबों रु. लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों एक नकारा किस्म के रिटायर्ड आईएएस को अहमदाबाद में लिक्विडेटर बना रखा है। इसे जब लोग टेलीफोन करते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास स्टाफ नहीं है। उसे जानबूझकर इसलिए बैठा रखा है ताकि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो।

भाजपा की निलम्बित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को दोहरी रात

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एस.एल.पी. खारिज की और हाई कोर्ट ने सरकार के निलम्बन आदेश पर रोक लगाई

- ज्ञातव्य है कि, 7 फरवरी 2021 को मालपुरा पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित सोनिया सोनी को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राज्य सरकार ने निलम्बित कर दिया था।

मालपुरा (निस), फरवरी 2021 को निर्वाचित हुई भाजपा की मालपुरा नगरपालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट से दोहरी राहत मिली। ज्ञातव्य है कि सोनी को दो बार निलम्बित कर चुकी राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एस.एल.पी. दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने सोनिया सोनी को दोबारा निलम्बित किये जाने के आदेश पर रोक लगा दी, इस प्रकार सोनिया सोनी को दोहरी राहत मिली।

सोनिया सोनी के वकील लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि 7 फरवरी 2021 को भाजपा से मालपुरा पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई सोनिया सोनी को राज्य सरकार ने 4 मई 2022 को भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निलम्बित कर दिया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 अगस्त 2022 को सोनिया सोनी की याचिका को मंजूर कर दिया, और राज्य सरकार के निलम्बर आदेश पर रोक लगा दी। फिर राज्य सरकार ने खण्डपीठ में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी। खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर स्थगन दे दिया। पर 6 जनवरी 2023 को स्थगन आदेश इसके बाद हटा दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की। एस.एल.पी. दायर किये जाने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस मनोज मिश्रा की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने सरकार की एस.एल.पी. को खारिज कर दिया। वही राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने सोनिया सोनी को 7 अक्टूबर को दोबारा निलम्बित करने के सरकार के आदेश के विरूद्ध दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी। प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण मंगलवार को सोनिया सोनी व उनके पति मनीष सोनी ने स्वंय अपना पक्ष रखा। करीब आधा घंटे तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निलम्बन आदेश पर रोक लगा दी तथा तत्काल प्रभाव से कार्य ग्रहण करने के आदेश पारित किये। मंगलवार को दोनों ही न्यायालयों से सोनिया को मिली दोहरी राहत पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मंगलवार के दिन को एतिहासिक बताया और कहा भाजपा के मालपुरा पालिका सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।

पाकिस्तान ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुसाइड बॉम्बिंग और चुनिंदा लोगों की हत्याएं शामिल थीं।

वर्ष 2018 में पाकिस्तान को वर्ष 1998 के इन्टरनैशनल रिलीजस फ्रीडम एक्ट के तहत कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कन्सर्न (सी.पी.सी.) के रूप में नामित किया गया। उसे वर्ष 2019, 2020 और 2021 में पुनः सी.पी.सी. माना गया। वर्ष 2018 में व फायनैशियल एक्शन तस्क फोर्स (एफ.ए.टी.एफ.) ने पाकिस्तान को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया ए.एम.एल./सी.एफ.टी. सिस्टम में प्रमुख कमियां हैं और उसने उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया। यह पड़ोसी देश वर्ष 2021 तक एफ.ए.टी.एफ. की ग्रे लिस्ट में रहा। वर्ष 2021 में पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्याओं को आतंकवादी गुटों की कठोर धमकियों था सामना करना पड़ा। आई.एस.आई.एस. के उग्रवादियों ने बलूचिस्तान के काछी जिले में स्थित कोपला खदानों में काम करने वाले शिया हाज़रा पंथ के 11 लोगों की हत्याओं की जिम्मेदारी ली। बलूचिस्तान के ही क्वेटा स्थित सिरीना होटल की पार्किंग में 21 अप्रैल को पांच जने एक वी.बी.आई.ई.डी. सुसाइड अटैक में मारे गए। जांच पड़ताल के ब्योरे के अनुसार हमले का निशाना स्थानीय और विदेशी अधिकारी थे। ब्यूरो ऑफ काउन्टरटैरेज़्मि की रिपोर्ट ऑन टैरेरिज़्म इन पाकिस्तान के अनुसार टी.टी.पी. ने उक्त हमले की जिम्मेदारी ली और यह भी दावा किया कि उसका निशाना पुलिस और कानून प्रवर्तन से जुड़े लोग थे।

इसके अलावा, 10 अक्टूबर 2021 को बलूचिस्तान में हुए एक बम विस्फोट में पाकिस्तान का एक प्रमुख पत्रकार मारा गया और 30 दिसम्बर 2021 को हमलावरों ने नॉर्थ वजीरिस्तान में सुरक्षा बलों के अधिकारियों पर घात लगाकर हमला किया। उसके बाद हुई आपसी फायरिंग में चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 1997 के एंटीटैरेरिज़्म एक्ट द नैशनल काउन्टरटैरेरिज़्म ऑथोरिटी एक्ट, वर्ष 2014 के इन्वैस्टिगेशन फोर फेयर ट्रायल एक्ट और एंटीटैरेरिज़्म एक्ट में वर्ष 2014 और 2020 में किए गए अहम संशोधनों आदि का क्रियान्वयन जारी रखा। इन सभी कानूनों के कानून प्रवर्तन एजेन्सियों, अभियोजकों और कोर्टों को आतंकवादी केसों को लेकर अधिक शक्तियां प्रदान की।

रिपोर्ट के अनुसार सेना, अर्द्धसैनिक बलों और नागरिक सुरक्षा सेनाओं ने पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अभियान चलाए। पाकिस्तानी कानून में आतंकवादी अपराधों के लिए जेल और मौत की सजा तक का प्रावधान है। वहां आतंकवादी केसों की अलग से सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ मदरसों में चरमपंथी सिद्धान्त पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार जहां प्रयास कर रही है, वहीं कुछ विश्लेषक और मदरसा सुधारकों का मानना है कि कई मदरसे सरकार में अपना पंजीकरण कराने, अपनी फण्डिंग के स्रोतों के दस्तावेज उपलब्ध करवाने और विदेशी छात्रों की स्वीकार्यता संबंधी कानूनों की अनुपालना में विफल रहे है।

राजस्थान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह याचिका किसी छाया रानी की ओर से एडवोकेट विशाल तिवारी व अभिगा कुशवाह ने दायर की है।

याचिकाकर्ता के अभिवक्ताओं ने शीर्ष अदालत को बताया कि राजस्थान स्टाफ सलैक्शन बोर्ड के नियमनों के अधीन परीक्षा का संचालन करने के लिए भरतपुर के संभागीय आयुक्त ने गत 24 फरवरी को एक आदेश जारी कर जयपुर, भरतपुर व अन्य कई जिलों में इंटरनैट सेवाएं निलम्बित कर दी थीं। याचिका में मांग की गई कि कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन के केस में दी गई व्यवस्था के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद -21 में वर्णित मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जाए, खासतौर पर जीवन स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि आशंका आधारित मनमाने और अधिकार रहित इंटरनैट शट डाउन्स को रोका जाए क्योंकि इससे जनता प्रभावित होती है, न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि अनुराधा भसीन के केस में उसके द्वारा दी गई गाइडलाइन्स की तुरन्त प्रभाव से पालना करवायी जाए।

तेलंगाना के भाजपा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का उल्लेख दस्तावेजों में हैं तथा एक शराब कंपनी में उनके 65 प्रतिशत शेयर हैं। कविता ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है तथा इन्हें पूरी तरह बोगस एवं झूठे बताया है। लेकिन यह तो साफ है कि पार्टी के जनसम्पर्क अभियान में, भाजपा के प्रचार के सुर और तेवर के.सी.आर. तथा उनके परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमले वाले रहेंगे।

ऐसी योजना बनाई जा रही है कि जन सम्पर्क अभियान बड़े पैमाने पर चलेगा तथा इस अभियान में "प्रजा घोष", "भाजपा भरोसा" तथा "प्रजा संग्राम यात्रा" जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे तथा ऐसी आशा की जा रही है कि इन कार्यक्रमों के फलस्तरुप, मतदाताओं में राजनैतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी।

इस प्रकार के कार्यक्रमों से पार्टी को इस तेलुगु भाषी राज्य में अपनी जड़ें जमाने में मदद मिलेगी। भाजपा को आशा है कि वह अच्छे प्रदर्शन से कहीं ज्यादा असर पैदा करने में सफल होगी। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल इस साल के अंतिम महीनो में पूरा हो रहा है तथा उसके बाद राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिये चुनाव होंगे।

कर्नाटक के अलावा, तेलंगाना एक ऐसा राज्य है, जहाँ भाजपा को चुनौती देने की स्थिति, बल्कि सत्ता में आने तक की संभावना दिखाई दे रही है।

एक बात तो पक्की हैं तथा एक भाजपा नेता ने ऐसा कहा भी है कि भाजपा नेता पूरे तेलंगाना में "माहौल बनाने" के लिये, बड़े पैमाने पर जबरदस्त रैलियां एवं सभाएं आयोजित करेगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी दो-चार बार राज्य का दौरा करेंगे।

मनीष सिसोदिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से इस केस का उल्लेख किये जाते ही कह दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय, सिसोदिया के पास राहत पाने के और भी विकल्प हैं।

सी.जे.आई. तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की इस बैंच ने सिसोदिया को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। बैंच सिंघवी के यह कहने से भी प्रभावित नहीं हुई कि सिसोदिया को जमानत न मिलने से दिल्ली सरकार का काम रूक जायेगा क्योंकि सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों का कार्यभार है।

जब सिंघवी ने इस मुद्दे पर दबाव डालते हुये कहा कि ऐसे अलग-अलग 32 उदाहरण हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के केसों की सुनवाई की हैं तो सी.जे.आई. शिव सेना प्रकरण में संविधान पीठ की बैठक के बाद, गुरुवार को अपरान्ह 3.50 बजे इसकी सुनवाई के लिये सहमत हो गये।

सी.जे.आई. ने यह भी कहा कि अदालत ने पिछले सप्ताह पवन खेड़ा के केस में हस्तक्षेप किया था क्योंकि कई राज्यों में दर्ज की गईं एफ.आई.आर. को इकट्ठा कर लेने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने पूछा, "जब वे (सिसोदिया) सभी अवसरों पर उपस्थित हुये हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? फ्लाइट रिस्क कहाँ है?" सिंघवी ने कहा कि रिमान्ड इसी आधार पर ली गई है कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि क्या सहयोग का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति उस पर लगाये गये अभियोग के खिलाफ अपने स्वयं को दोषयुक्त बताने का अधिकार छोड़ दे।

'राजस्थान में पेपरलीक और इन्टरनैट बंद क्यों होता है?'

- कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने पेपर लीक और इन्टरनैट बंद करने पर सरकार से सवाल किया।
- उन्होंने कहा, यूक्रेन में युद्ध के बीच भी इन्टरनैट चालू है, लेकिन राजस्थान की हर परीक्षा में नैट बंद कर देते हो।
- हरीश मीणा ने कहा, आई.ए.एस.-आई.पी.एस. परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता, न केन्द्र सरकार नैट बंद करती है।
- उन्होंने कटाक्ष किया, "आर.पी.एस.सी. से पेपर लीक होते हैं या कहीं और से, कुछ पता तो लगाओ, नाकामी छुपाने के लिए इन्टरनैट बंद कर देते हो।"

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपरलीक और इंटरनैट बंद करने पर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से पूछा कि, आखिर राजस्थान में ही भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक क्यों होते हैं? सरकार आज तक मालूम नहीं लगा पाई कि आर.पी.एस.सी. से पेपर लीक होता है या फिर कहीं और से। सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए इंटरनैट बंद कर देते हैं।

गृह व कारागार की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए हरीश मीणा ने कहा कि राजस्थान में ही पेपरलीक और इंटरनैट बंद क्यों होता है? यूक्रेन में युद्ध के बीच नेट चालू है। हमारे यहां परीक्षा होते ही नैट बंद कर देते हैं।

हरीश मीणा ने कहा, कुछ चीजें राजस्थान में नई हो रही हैं, जैसे पेपरलीक। मैं भी राजस्थान का मूल निवासी हूं। मैंने भी पेपर दिए हैं। यू.पी.एस.सी. की परीक्षा पूरे देश में होती है। मैंने तो नहीं सुना कि आईएएस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इंटरनैट बंद करने से कुछ नहीं होगा, कारणों पर जाइए। इसका मुख्य कारण यह है कि, हम लोग अपराधियों तक नहीं पहुंच रहे। यह राजस्थान का आंतरिक मामला है। राजस्थान में ही पेपर छपते हैं। राजस्थान के ही लोग एग्ज़ाम देते हैं। राजस्थान के ही लोग पेपरलीक करते हैं। आज तक पता नहीं लगा पाए कि पेपर लीक आर.पी.एस.सी. से होता है, या कहां से होता है, कुछ तो पता लगाइए।

हरीश मीणा ने कहा कि दुनिया भर में जितना इंटरनैट बंद होता है, उसका आधा भारत में होता है। उन्होंने कहा, इंटरनैट बैन करने में राजस्थान, भारत में टॉप पर है। यह सर्वे आज ही छपा है। यह मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। चिंता की बात है। इस पर मंथन करना चाहिए। इसका समाधान निकालना चाहिए। हर चीज को डिफेंड करने से पार नहीं पड़ेगी।

हरीश मीणा ने कहा, हरियाणा में दो युवकों को जिंदा जला दिया। आज उनके गांव घाटमीका में उनके समाज के लोगों ने मीटिंग रखी और वहां इंटरनैट बंद कर दिया। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। व्यापारियों का व्यापार चल रहा है। आप नैट बंद कर रहे हो। सोमवार को जयपुर शहर के व्यापार मंडल ने मीटिंग की थी। उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि, 2 दिन की नैटबंदी से करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या तरीका है यह? थोड़ा सा तो ध्यान रखें। अपराध रोकना है या व्यापार रोकना है? कहीं दुनिया में यह नहीं होता कि आप बात-बात में इंटरनैट बंद कर दें। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां भी इंटरनैट चालू है। हमारे यहां परीक्षा होते ही इंटरनैट बंद, क्या साबित करना चाहते हो? जो भी यह कर रहे हो अच्छा नहीं है। इसका कोई और समाधान निकाले।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्स:01562-256908